सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 23 JANUARY TO 29 JANUARY 2026 • VOLUME 27 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

"शिकायतें आपको वहीं रोक देती हैं जहाँ आप खड़े हैं; कोशिशें आपको वहाँ ले जाती हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	16°	8°
शनिवार	15 °	6°
रविवार	19°	6°
सोमवार	20°	7°
मंगलवार	15°	7°
बुधवार	15°	7°
वीरवार	17°	6°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?
What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost
E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

गहरी खाई में गिरा सेना का ट्रक 10 जवान शहीद, 11 घायल

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के डोडा में वीरवार को भारतीय सेना का एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस भीषण दुर्घटना में 10 जवानों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य जवान घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार यह हादसा भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय मार्ग पर खन्नी टॉप के पास हुआ।

सेना का वाहन नियमित आवाजाही के दौरान पहाड़ी रास्ते पर अचानक सड़क से फिसल गया और सीधे गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में कुल 21 जवान सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि बुलेट-प्रूफ सेना का वाहन एक ऊँची पोस्ट की ओर जा रहा था, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और वाहन 200 फुट गहरी खाई में गिर गया।

सेना और पुलिस द्वारा तुरंत एक संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया गया और अधिकारियों ने बताया कि दस जवानों के शव मिले। उन्होंने बताया कि 11 अन्य जवानों को घायल हालत में बचाया गया और उनमें से जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें विशेष इलाज के लिए उधमपुर सैन्य अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया।

पीएम मोदी ने दुःख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डोडा में हुए दुखद हादसे में बहादुर सैन्यकर्मियों की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि डोडा में हुए हादसे से मैं अत्यंत व्यथित हूं, जिसमें हमने अपने बहादुर सैन्यकर्मियों को खो दिया। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव याद रखा जाएगा। मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

सीएम द्वारा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुखद हादसे पर शोक व्यक्त किया, जिसमें 10 सेना के जवान शहीद हो गए। मुख्यमंत्री कार्यालय की पोस्ट में लिखा था, मुख्यमंत्री ने भदरवाह-चंबा मार्ग पर खानीटॉप में सेना के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए त्वरित बचाव और राहत कार्यों की सराहना की।

पूरा देश शोक संतृप्त परिवारों के साथ खड़ा : एलजी

एलजी मनोज सिन्हा ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस गहरे दुख की घड़ी में पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता और समर्थन में खड़ा है। 11 घायल जवानों को अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

पंजाब में हर परिवार को मिलेगा 10 लाख तक मुफ्त इलाज

• **जालंधर ब्रीज.** मोहाली

राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को मोहाली में 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' की शुरुआत की, जिससे राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना के लागू होने से अमीरों की पहुंच में आने वाले सबसे महंगे निजी अस्पताल भी गरीबों के लिए खोल दिए गए हैं, जो लोक सेवा में निर्णायक बदलाव है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्ता की भूखी विपक्षी पार्टियां आपसी लड़ाइयों में डूबी रहती हैं और सिर्फ 'आप' ही पंजाब का भविष्य सुरक्षित कर सकती है। इस मौके पर 'आप' कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कुछ योग्य लाभार्थियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना कार्ड भी सौंपे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य

योजना की शुरुआत के दौरान 'आप' के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन है।

'आप' सुप्रीमो ने कहा कि पिछले 75 सालों में बहुत सारी सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनमें से किसी ने भी लोगों की परवाह नहीं की। बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन लोगों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पंजाब आतंकवाद से ग्रस्त था और फिर एक ऐसा दौर आया जब नशे की दलदल में फंस गया था। उन्होंने कहा, "हर चीज का अपना समय होता है। पिछले चार सालों से पंजाब जिस दौर से गुजर रहा है, वह पंजाब और देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।"

अरविंद केजरीवाल ने बताया, "बड़ी और छोटी बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक की सारी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त होंगे। जैसे ही मरीज अस्पताल में दाखिल होता है, सब कुछ मुफ्त होगा। उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ अपना हेल्थ कार्ड लाने के लिए। पंजाब में लगभग 65 लाख परिवार हैं, जिनमें अमीर और गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल हैं। 'आप' प्रमुख ने आगे कहा कि पहले पंजाब के सरकारी अस्पतालों को डॉक्टरों की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। पिछले चार सालों में 1100 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की गई है और अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है।

ऑपरेशन प्रहार : पहले चरण में 3256 व्यक्ति काबू

लोग गैंगस्टर विरोधी हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों के बारे में सूचना दे सकते हैं : डीजीपी

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

'गैंगस्टरां ते वार' के पहले चरण के तहत शुरू किए गए 72 घंटे के 'ऑपरेशन प्रहार' को बड़ी सफलता मिली है। इसके परिणामस्वरूप विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के पंजाब में मौजूद साथियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि 'गैंगस्टरां ते वार' एक निरंतर अभियान है, जो तब तक इसी तरह जारी रहेगा जब तक पंजाब से गैंगस्टरों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। तीन दिन चले इस ऑपरेशन के नतीजे साझा करते हुए स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने कहा कि

पूरे राज्य में कुल 4871 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 3256 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने इनके कब्जे से 69 हथियार, 6.5 किलो हेरोइन, 10.5 किलो अफीम, 5092 नशीली गोलियां, 72 किलो भुक्की और 2.69 लाख रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुलिस टीमों ने 80 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है और 25 एहतियातन गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

स्पेशल डीजीपी ने बताया कि 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब गैंगस्टरों से मुक्त नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से लोग गुप्त रूप से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में सूचना दे सकते हैं और अपराध व आपराधिक गतिविधियों की जानकारी साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किसी गैंगस्टर की गिरफ्तारी होती है, तो उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक की इनाम राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।

1 करोड़ के इनामी अनल समेत 16 नक्सली ढेर

नई दिल्ली (जालंधर ब्रीज). केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस द्वारा चल रहे एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 करोड़ रुपये का कुख्यात इनामी नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर 'अनल उर्फ पतिराम मांझी' और 15 अन्य नक्सलियों के अब तक एनकाउंटर से नक्सलमुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली। दशकों से भय और आतंक के पर्याय रहे नक्सलवाद को हम 31 मार्च 2026 से पहले समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं। मेरी पुनः शेष बचे नक्सलियों से अपील है कि हिंसा, आतंक और हथियारों से जोड़ने वाली विचारधारा को छोड़ विकास और विश्वास की मुख्यधारा से जुड़ें।"

सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुरा की प्रिंसिपल को निलंबित करने के आदेश

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी करते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरादपुरा, जिला अमृतसर की प्रिंसिपल रेखा महाजन को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि प्रिंसिपल रेखा महाजन द्वारा डी.पी.ई. अध्यापक जोरिंदर सिंह के लिए जातिसूचक शब्दावली का प्रयोग किया गया था। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा गठित दो सदस्यीय कमेटी द्वारा भी रेखा महाजन के खिलाफ शिकायत को सही पाया गया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और 29 जनवरी 2026 को केस संबंधी डायरेक्टर सेकेंडरी शिक्षा विभाग से व्यक्तिगत पेशी के दौरान रिपोर्ट मांगी गई है।

रिश्वत लेने के आरोप में वन गार्ड सहित तीन गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग के दफ्तर जिला नवांशहर में तैनात वन गार्ड तेजिंदरपाल सिंह, वन विभाग के दफ्तर जिला नवांशहर में तैनात शमशेर सिंह (दिहाड़ी मजदूर) और जिला एस.बी.एस. नगर के निवासी चाय बेचने वाले अमरजीत थिंद को 1,10,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान उक्त कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके चलते विजिलेंस ब्यूरो यूनिट एसबीएस नगर ने इन मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग दफ्तर नवांशहर के ब्लॉक अफसर चिराग लखोतरा के घर और अन्य स्थानों पर छापेमारी करने के लिए टीमें गठित की हैं ताकि उसे जल्द ही गिरफ्तार

किया जा सके। इस संबंध में यदि वन विभाग के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई सबूत सामने आता है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में इन मुलजिमों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी मानव एकता के आध्यात्मिक प्रकाश और बलिदान की भावना का प्रतीक

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). गणतंत्र दिवस परेड-2026 के लिए पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गई झांकी मानव एकता, दया-भावना और धार्मिक मूल्यों के उच्चतम आदर्शों को बनाए रखने के लिए आध्यात्मिकता और बलिदान की निस्वार्थ भावना का अनूठा प्रतीक है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि झांकी के दो हिस्से हैं- ट्रैक्टर और ट्रेलर। झांकी के ट्रैक्टर हिस्से में हाथ का निशान बना हुआ है। आगे के हिस्से में 'एक ओंकार' (परमात्मा एक है) का निशान है और कपड़े का एक टुकड़ा जिस पर 'हिंद दी चादर' की उकेरी हुई लिखावट है। ट्रेलर वाले हिस्से में रागी सिंहों द्वारा 'शब्द कीर्तन' किया जा रहा है, जिसके पिछले हिस्से में 'खंडा साहिब' का निशान है। यह स्थान दिल्ली के गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब के ठीक सामने सुशोभित है और इस चौक पर

रोजाना शब्द कीर्तन होता है। ट्रेलर वाले हिस्से के किनारे पर गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब का मॉडल सुशोभित है, जिस स्थान पर नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी को शहीद किया गया था। साइड पैनल गुरु साहिब के श्रद्धालु सिख भाई मती दास जी, जिन्हें जिंदा आरे से चीरकर शहीद किया गया था, भाई सती दास जी, जिन्हें ऊन में लपेटकर जिंदा जला दिया गया था और भाई दयाला जी, जिन्हें उबलती देग में डालकर शहीद किया गया था, की शहादत को दर्शाते हैं।

जीएसटी बिलिंग घोटाले में पिता-पुत्र गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** लुधियाना

विशेष खुफिया सूचना के आधार पर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कमिश्नरेट, लुधियाना के अधिकारियों ने 19 जनवरी 2026 को लुधियाना में कई तलाशी अभियान संचालित किए, जिनमें 311 करोड़ रुपये के बड़े नकली जीएसटी चालान घोटाले का खुलासा हुआ। लोहे और इस्पात क्षेत्र की एक प्रमुख निर्माण कंपनी ने इन नकली जीएसटी चालानों का लाभ उठाकर 47.50 करोड़ रुपये के अवैध इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का इस्तेमाल अपनी जीएसटी देनदारियों की पूर्ति में किया, जिससे सरकारी राजस्व को काफी नुकसान हुआ।

तलाशी अभियानों के उपरांत, पिता-पुत्र की जोड़ी, जो इन फर्मों का संचालन और नियंत्रण कर रहे थे, केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के

तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पूरी जांच अभी जारी है, ताकि इस घोटाले के नेटवर्क का पूरा दायरा उजागर किया जा सके और इसमें शामिल अन्य संस्थाओं की पहचान की जा सके।

सीजीएसटी लुधियाना कमिश्नरेट कर धोखाधड़ी का पता लगाने तथा ईमानदार करदाताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को पुनः दोहराता है।

सीजीएसटी लुधियाना द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ₹93 करोड़ की जीएसटी वसूली

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), लुधियाना के अधिकारियों ने एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर के विरुद्ध चल रही जांच के दौरान 10 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की है। यह जांच विकास प्रयोजन हेतु दीर्घकालिक पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अदा किए गए अग्रिम पट्टा प्रीमियम पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म (आरसीएम) के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कथित गैर-भुगतान से संबंधित है। जांच की अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की है।

जांच के दौरान करदाता द्वारा अपनी जीएसटी देयता के विरुद्ध स्वेच्छा से 10 करोड़ रुपये की राशि इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से जमा करवाई गई।

कर अनुपालना को प्रोत्साहित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के अपने प्रयासों के तहत, केंद्रीय जीएसटी, लुधियाना द्वारा विभिन्न प्रवर्तन उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 93 करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली की जा चुकी है। मामले में आगे की जांच जारी है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) 2026 के दौरान चुनावों से संबंधित सभी जानकारियों और सेवाओं के लिए अपने वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट का शुभारंभ किया। यह तीन दिवसीय सम्मेलन 21 से 23 जनवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। ईसीआई-नेट की संकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी द्वारा की गई थी और इसके डिजाइन की घोषणा मई 2025 में की गई थी।

ईसीआई-नेट के लॉन्च के अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म को कानूनों के सख्त अनुपालन के तहत विकसित किया गया है और यह 22 भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है। उन्होंने दुनिया भर की चुनाव प्रबंधन संस्थाओं को अपने-अपने देशों के कानूनों के अनुरूप, अपनी संबंधित भाषाओं में ऐसे

ही डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने की पेशकश की है।

निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि ईसीआई-नेट चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है, क्योंकि यह अधिक पारदर्शिता लाने, समग्र प्रक्रियाओं की निगरानी, त्वरित निर्णय लेने तथा सूचना के प्रभावी प्रसार में सहायता करता है। निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि यह सम्मेलन चुनाव प्रबंधन संस्थाओं (ईएमबीज़) को प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों को अपनाने से जुड़े वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखने का अवसर प्रदान करेगा।

दुनिया घूमकर भी कमा सकते हैं नाम और पैसा, जानें कैसे बनें सफल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर

Travelling घूमने का शौक रखते हैं, तो इसे आप कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। जी हां, नई जगहों पर घूमने-फिरने का पैशन है, तो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। चलिए बताते हैं इसके लिए किन बातों का ध्यान...

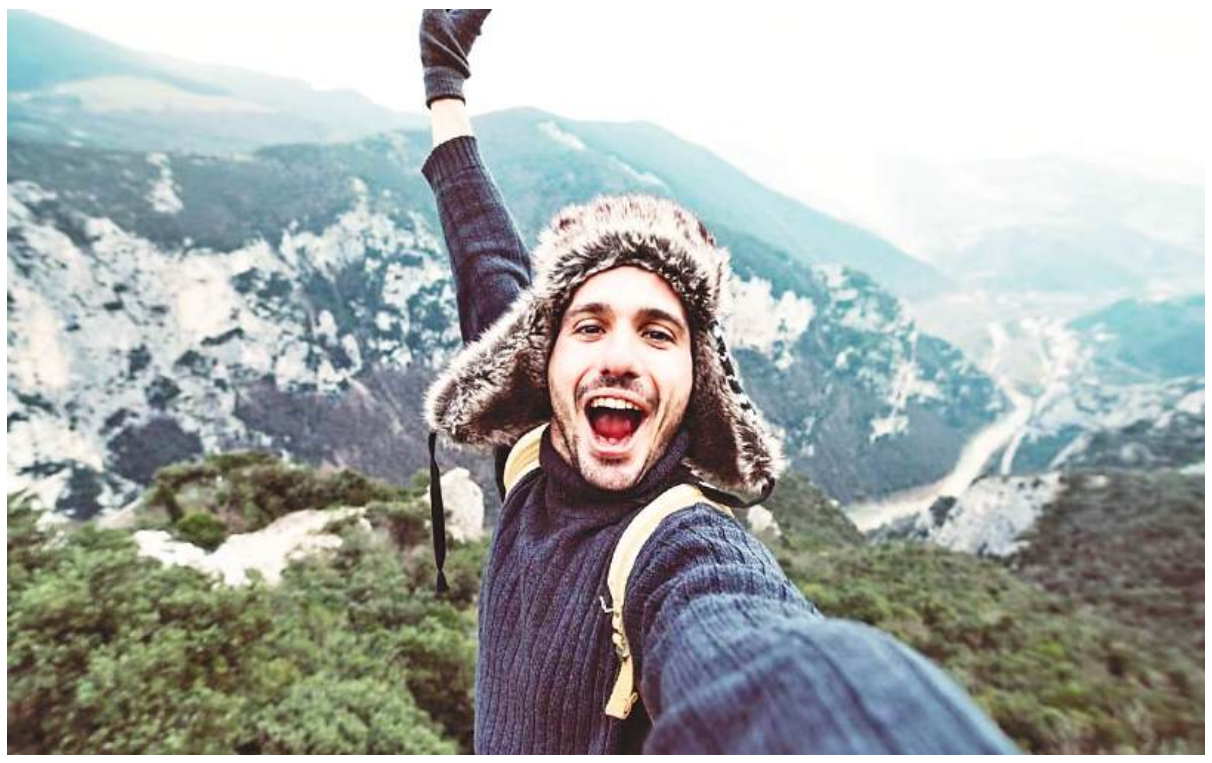

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई खुद की वीडियो या ब्लॉगिंग करके पोस्ट करता रहता है। रील्स-पोस्ट पर आने वाले व्यूज और पेड प्रमोशन से लोग नाम और पैसा कमा रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज का इन्फ्लुएंसर बनना इतना भी आसान नहीं है, इसके पीछे कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अगर आपको घूमना पसंद हैं, तो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इसमें आप देश-दुनिया की सैर करें और अपना नाम बनाएं। लोगों को घूमना काफी पसंद है और कही भी घूमने जाने से पहले लोग उस जगह के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं। ऐसे में ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के वीडियो उनकी मदद करते हैं, उस जगह की पूरी जानकारी देने में। लेकिन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सब हम बताने जा रहे हैं।

कैसे बनें ट्रैवल इन्फ्लुएंसर

1- ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना नीचे (लक्ष्य) सेट करना होगा। मतलब आप क्या बाकि लोगों से हटकर पब्लिक को दे रहे हैं। कई ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपने काम में परफेक्ट हैं। उनके बीच कुछ अलग करने के लिए आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी जगह की बारीक डिटेल्स को कवर करें, आइटनरी बताएं, ट्रिप कॉस्ट या किसी भी जगह के फेमस स्पॉट्स के बारे में। आप कोई भी एक चीज चुनकर उसी पर फोकस करते हुए वीडिया बनाना शुरू करें। इसके लिए आप अच्छे कैमरे वाला फोन या कैमरा लें। लैपल या वायरलेस माइक खरीद लें।

2- ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने के साथ आपको फोटो-वीडियो भी अच्छी बनानी आनी चाहिए। इससे आप किसी भी जगह की सुंदर फोटोज खींचकर रील्स-पोस्ट में शेयर करें। कहते हैं तस्वीर सौ शब्दों के बराबर होती है। ऐसे में आपकी तस्वीर भी जगह की खूबसूरती को दिखाने और सामने वाले की आंखों पर छाने का काम कर सकती हैं।

3- सिर्फ अच्छी जगह और फोटो क्वालिटी से आप अच्छे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको परफेक्ट स्टोरीटेलिंग भी आनी चाहिए। आप उस जगह के बारे में क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं सबकुछ ध्यान में रखते हुए स्टोरी बतानी है।

4- अपनी वीडियो में सिर्फ जगह के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों के काम की जानकारी भी दें, जैसे कहां रुक सकते हैं, कितना खर्चा, कहां खाएं। कई लोग इस तरह के कंटेंट के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर बार-बार आपकी वीडियो देखेंगे।

5- हफ्ते में 3-4 रील्स, पोस्ट जरूर शेयर करें। इससे यूट्यूब-इंस्टाग्राम का एल्गोरिद्म व ऑडियंस आप से अच्छे से कनेक्ट कर लेगी। इसके साथ SEO का ध्यान रखें। जैसे इंस्टा-फेसबुक-यूट्यूब पर हैशटैक क्या यूज करने हैं और डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए।

6- जब आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचने लगेगी, तब आपको की ब्रांड्स पेड प्रमोशन के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पैसे भी मिलेंगे। इसके अलावा कही भी जाने पर कुछ जगहों पर आपको फ्री होटल और फूड मिल सकता है। बस आपको मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहना है और वीडियो बनाने हैं। कई बार लोगों को सालभर बाद अच्छा रिजल्ट मिलता है और कुछ लोगों को महीने भर में ही। ये आपकी लगन और काम पर निर्भर करता है।

LIFESTYLE

बच्चे के बाल में जुएं पड़ गई तो केमिकल वाले शैंपू लगाने की बजाय लगाएं ये होममेड ऑयल, जूं-लीख दोनों का

बच्चे के बाल में जूएं पड़ गई हैं तो इन्हें भगाने के लिए किसी केमिकल वाले शैंपू या तेल को बच्चे के सिर की स्कैल्प पर ना लगाएं। बल्कि ये होममेड हेयर ऑयल को लगा दें। जिससे बालों से जुएं के साथ लीख भी आसानी से मर ...

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

बच्चों के साथ हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के सिर में जुएं पड़ना बिल्कुल आम बात है। वहीं बड़ों के सिर में भी कई बार ये पड़ जाती हैं। जूं का नाम सुनते ही सिर में खुजली महसूस होने लगती है।

ये जुएं बालों में रहकर खून चूसती हैं बड़ी ही तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाती हैं। एक बार में एक जूं करीब 5 अंडे देती है। और हर दिन अपनी संख्या बढ़ाती चली जाती हैं। ऐसे में बालों में पनपते ही इनका सफाया सही समय पर करना जरूरी है। नहीं तो ये एक से दूसरे सिर में भी चढ़ना शुरू कर देती हैं। बालों में जुएं हो गई हैं तो इनसे निपटने के लिए बाजार में केमिकल वाले शैंपू और तेल लगाना बच्चों की स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में ये घर में बने हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। जो तेजी से बालों की जूं और लीखों (अंडे के बच्चों) दोनों का सफाया करता है।

- जुएं भगाने के लिए बनाएं घर में होममेड ऑयल
- बालों की जूं भगानी है तो केमिकल वाले हेयर ऑयल बच्चों के स्कैल्प पर लगाने की बजाय घर में बना ये हेयर ऑयल लगाएं।
- जुएं भगाने वाले होममेड हेयर ऑयल को बनाने के लिए किसी बर्तन में सरसों का तेल लें।
- तेल को गैस पर चढाएं और उसमे आठ से दस लौंग और एक चम्मच मेथी के दाने को डाल दें। अब इसे गर्म करें।
- जब तेल गर्म होने लगे तो दो टिकिया कपूर की बारीक पाउडर बनाकर डाल दें।
- अब इस तेल को तब तक गर्म करें जब तक लौंग बिल्कुल काली ना होने लगे।
- गैस की फ्लेम को बंद कर दें और तेल को छानकर ठंडा कर लें।
- किसी बोतल में भरकर रख दें। जिस भी बच्चे के सिर में जुएं है उसके बालों में ये लौंग और कपूर से बने तेल को लगाएं।
- फिर जुएं वाली स्पेशल कंघी से बालों को साफ करें। ऐसा करने से जूं मरकर आसानी से बाहर आ जाएंगी।
- जिन बच्चों के बाल घने होते हैं और जूं पड़ी रहती है उन्हें ये तेल लगाकर बार-बार कंघी से सफाई करने से कुछ ही दिनों में सारे जूं का सफाया हो जाता है। साथ ही लीख भी मरना शुरू कर देती हैं।

डिस्क्लेमर : इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें। किसी भी बीमारी के लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

ठंड में हेल्दी और कंफर्ट फूड चाहिए? ट्राई करें ये आसान आलू सूप रेसिपी

सर्दियों में शरीर को गर्माहट और पोषण दोनों चाहिए। ऐसे में आलू से बना क्रीमी सूप न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि इम्युनिटी और एनर्जी भी देता है। जानिए घर पर आसान विधि।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो अंदर से गर्म रखें और साथ ही पोषण भी दें। ऐसे में गरमा-गरम सूप सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। आलू का सूप ना केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि यह शरीर को तुरंत ऊर्जा भी देता है। यह सूप बच्चों, बुज़ुर्गों और ठंड में जल्दी थक जाने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को गर्माहट देने में मदद करते हैं, वहीं दूध और बटर सूप को क्रीमी बनाकर उसे एक परफेक्ट कंफर्ट फूड बना देते हैं। सर्दियों में जब पाचन थोड़ा धीमा हो जाता है, तब यह सूप हल्का होने के कारण आसानी से पच जाता है और पेट पर भारी भी नहीं पड़ता।

आवश्यक सामग्री :

- उबले हुए आलू - 3
- बटर - 1 टेबलस्पून
- लहसुन - 4-5 कलियां (बारीक कटी)
- प्याज - 1 छोटा (बारीक कटा)
- मैदा - 1 टेबलस्पून
- दूध - 1 कप
- सब्ज़ी स्टॉक या पानी - 2 कप
- नमक - स्वादानुसार
- काली मिर्च पाउडर - ½ टीस्पून
- फ्रेश क्रीम - 2 टेबलस्पून
- हरा धनिया या स्प्रिंग अनियन - सजाने के लिए

बनाने की विधि

- सबसे पहले आलू को उबालकर अच्छी तरह मैश कर लें। अब एक गहरे पैन में बटर गरम करें और उसमें लहसुन व प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद मैदा डालकर धीमी आंच पर 1 मिनट तक चलाते रहें ताकि कच्चापन खत्म हो जाए।
- अब धीरे-धीरे दूध डालते जाएं और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें ना बनें। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब इसमें मैश किए हुए आलू और सब्जी स्टॉक डाल दें। सूप को मध्यम आंच पर 8-10 मिनट तक पकने दें।
- अंत में नमक, काली मिर्च और फ्रेश क्रीम डालकर अच्छे से मिलाएं। गैस बंद करें और ऊपर से हरा धनिया या स्प्रिंग अनियन डालकर गरमा-गरम परोसें।
- सर्दियों में यह आलू का सूप ना सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने और दिनभर एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करता है। ठंडी शामों में इसे ब्राउन ब्रेड या क्रैकर्स के साथ परोसें और सर्दियों के स्वाद का पूरा आनंद लें।

किताबों से दूर भागता है आपका बच्चा? ये हैं पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाले 5 बड़े कारण

PARENTING

जालंधर ब्रीज (फीचर) . आज के डिजिटल युग में माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बनी हुई है। ज्यादातर पेरेंट्स की यह शिकायत बनी हुई रहती है कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसका ध्यान इधर-उधर भटकने लगता है। माता-पिता बच्चे की एकाग्रता की कमी को उसकी 'लापरवाही' समझकर उसे डांटने लगते हैं, लेकिन हकीकत में उसका ध्यान भटकाने वाले कारक उसके भीतर नहीं बल्कि आस-पास के वातावरण में ही छिपे होते हैं। एक बच्चा जब किताब खोलकर बैठता है, तो उसके दिमाग में चल रहे गैजेट्स के शोर और सोशल मीडिया की चमक के बीच पढ़ाई की शांति कहीं खो जाती है। यह समझना बेहद जरूरी है कि एकाग्रता रातों-रात पैदा नहीं होती, बल्कि यह उन बाधाओं को हटाने से आती है जो बच्चे की मानसिक ऊर्जा को सोख रही हैं। आइए जानते हैं आखिर वो कौन से 5 कारण हैं, जो आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई से भटकाते हैं।

बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटकाने वाले मुख्य कारण : डिजिटल गैजेट्स और सोशल मीडिया- स्मार्टफोन, टैबलेट और वीडियो गेम्स जैसी चीजें आज बच्चों की एकाग्रता की सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर थोड़ी देर में आने वाले नोटिफिकेशंस बच्चे के 'डीप वर्क' (गहरी पढ़ाई) की लय को तोड़ देते हैं। जिससे बच्चे का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है।

- अधूरी नींद और थकान- यदि बच्चा 8-9 घंटे की भरपूर नींद नहीं ले रहा है, तो उसका मस्तिष्क जानकारी को प्रोसेस करने में असमर्थ रहता है, जिससे वह जल्दी पढ़ाई से ऊबने लगता है।
- पढ़ाई का तनाव और डर- जब बच्चे पर पेरेंट्स या शिक्षकों की तरफ से कक्षा में अच्छे अंक लाने का बहुत अधिक दबाव होता है, तो उसका दिमाग 'फ्लाइट मोड' में चला जाता है। डर के कारण वह विषय से दूर भागने की कोशिश करता है।
- अव्यवस्थित स्टडी एरिया- बच्चा जिस जगह बच्चा पढ़ रहा है, अगर वहां शोर-शराबा है, टीवी की आवाज या पढ़ने की टेबल का सामान बिखरा हुआ हो, तो भी बच्चे का ध्यान बार-बार अपनी किताबों से हटकर आस-पास की बिखरी हुई चीजों पर ही जाएगा।
- खानपान की खराब आदतें- बच्चों का बहुत ज्यादा शुगर या जंक फूड खाने से शरीर में ऊर्जा का स्तर अचानक बढ़ता- गिरता है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा महसूस करता है और पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता।

25 साल एक्सपीरिएंस वाले हार्ट सर्जन ने बताया 3 सप्लीमेंट्स को रखेगा हार्ट हेल्दी

Health हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ही कुछ हेल्दी सप्लीमेंट्स की भी जरूरत होती है। जैसे कि 25 साल एक्सपीरिएंस वाले कॉर्डियोवस्कुलर सर्जन ने बताए ऐसे ही 3 सप्लीमेंट्स जो हार्ट हेल्थ को...

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

इन दिनों लोगों को हार्ट से जुड़ी कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा। कब किसी को अचानक से दिल का दौरा पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसे में जरूरी है हार्ट हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए और जरूरी सावधानियों को फॉलो किया जाए। वैसे भी हार्ट बॉडी का सबसे जरूरी अंग है, जिसके खराब होते ही इंसान की मौत लगभग तय होती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल (स्मोकिंग, एल्कोहल,नो वर्कआउट, लांग सिटिंग) से दूर रहने के साथ ही कुछ हेल्दी सप्लीमेंट्स को भी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर कॉर्डियोवस्कुलर हेल्थ के डॉक्टर लंदन ने 3 हेल्थ सप्लीमेंट्स को बताया है। जिसे हार्ट फंक्शन और लांगेटिविटी बढ़ती है।

25 साल अनुभव वाले हार्ट सर्जन ने बताया 3 सप्लीमेंट्स जो रखेगा दिल का ख्याल

- कॉर्डियोवस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करने के बारे में डिस्कस करते हुए डॉक्टर लंदन ने बताया कि 3 सप्लीमेंट्स हार्ट हेल्थ को सही रखने में मदद करते हैं।

ओमेगा 3

- डॉक्टर लंदन ने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड में फैट लेवल को मैनेज करता है। ये ट्राईग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है और आंकड़े बताते हैं कि अगर ओमेगा 3 की मात्रा कम है और सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इससे कॉर्डियोवस्कुलर का रिस्क कम होता है।

को क्यू 10 (CoQ10)

- ये एक तरह का एंजाइम है जो बॉडी में हो रही मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में मददकरता है। हालांकि डॉक्टर लंदन कहते हैं कि ये ज्यादा एक्सप्टेबल नहीं है। लेकिन हार्ट फंक्शन के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं।

मैग्नीशियम

- हार्ट सर्जन ने मैग्नीशियम को भी कॉर्डियोवस्कुलर हेल्थ के लिए बेस्ट सप्लीमेंट बताया। मैग्नीशियम की कमी से इलेक्ट्रोलाइट इबैलेंस सबसे कॉमन है। चूंकि मैग्नीशियम मसल्स को आराम देता है। इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है और दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए भी जरूरी है।लेकिन साथ ही डॉक्टर ने बताया कि भले ही ये सप्लीमेंट्स फायदा पहुंचाते हों लेकिन बेसिक हेल्दी लिविंग के कॉन्सेप्ट से हार्ट को हेल्दी रखना और लंबी लाइफ के लिए फायदेमंद है। हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज और गुड स्लीप हाइजीन मेंटेन करना हमेशा वर्क करता है। ये सप्लीमेंट्स केवल आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने में मदद करते हैं।

डिस्क्लेमर : *यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।*

रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता जाल : क्या अब बड़े सुधारों का समय आ गया है?

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है।देश की बढ़ती खाद्य माँग को पूरा करने के उद्देश्य से पिछले कई दशकों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग निरंतर बढ़ाया गया है।शुरुआती दौर में इन उर्वरकों ने उत्पादन बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद की, लेकिन आज इनके अंधाधुंध और अनियंत्रित उपयोग के कारण कृषि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर संकट मंडराने लगा है।

उर्वरकों की खपत के भयावह आंकड़े

देश में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग का अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018-2019 में जहाँ 115 करोड़ बैग की खपत हुई थी, वहीं 2024-25 के दौरान यह आंकड़ा 150 करोड़ बैग को पार कर गया है।गौर करने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है, जबकि उर्वरकों की खपत 150 करोड़ बैग से भी अधिक हो चुकी है।यह असंतुलन न केवल चिंताजनक है, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़े खतरे का संकेत भी है।

सेहत और मिट्टी पर दोहरी मार

रासायनिक उर्वरकों का असर अब हमारे थाल तक पहुँच चुका है।गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ, फल और यहाँ तक कि दूध, दही और घी भी इनके रसायनों से अछूते नहीं रहे हैं।इसके परिणामस्वरूप देश में कैंसर, हृदय घात, एलर्जी और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

खेतों की स्थिति भी कम सोचनीय नहीं है।नियमानुसार, उर्वरकों का उपयोग केवल पौधों की जड़ों के पास होना चाहिए, लेकिन पूरे खेत में इनके छिड़काव से खरपतवार की समस्या बढ़ जाती है।इस खरपतवार को खत्म करने के लिए फिर भारी मात्रा में खरपतवार-नाशक दवाओं का उपयोग होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती हैं।मिट्टी की खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए किसान और अधिक खाद डालता है, और यह दुष्चक्र हर साल मिट्टी को और अधिक बंजर बनाता जा रहा है।

अर्थव्यवस्था पर बोझ और कालाबाजारी

उर्वरक क्षेत्र में बढ़ता निवेश देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ रहा है।वर्तमान में देश में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपये (सब्सिडी सहित) के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है।विडंबना यह है कि हमारा उर्वरक उद्योग 80 प्रतिशत तक विदेशी कच्चे माल या आयातित उर्वरकों पर निर्भर है।कुल 3 लाख करोड़ रुपये में से 2.5 लाख करोड़ रुपये केवल आयात में खर्च हो जाते हैं।इस

प्रकार, एक ओर हमारी भूमि बंजर हो रही है, तो दूसरी ओर देश की बड़ी पूंजी विदेशों में जा रही है।

सरकार किसानों के कल्याण के लिए भारी सब्सिडी दे रही है।पिछले 10 वर्षों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की गई है।इसी सब्सिडी के कारण 40 रुपये प्रति किलो वाली यूरिया खाद किसानों को 6 रुपये प्रति किलो से भी कम दाम पर उपलब्ध है।स्थिति यह है कि यूरिया आज पशुओं के चारे से भी सस्ता हो गया है।सरकार 85 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है ताकि किसानों को यूरिया एक चाय के कप से भी कम कीमत पर मिले।लेकिन इसी कम कीमत का लाभ उठाकर बिचौलिए इसकी कालाबाजारी करते हैं और कृषि के बजाय इसका उपयोग प्लाईवुड कारखानों, कैटल फीड और मिलावटी दूध बनाने में कर रहे हैं।

सुधार की राह और समाधान

इस संकट से उबरने के लिए अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।पहले खेतों से निकलने वाले अवशेषों का उपयोग जैविक खाद के रूप में होता था, जिससे मिट्टी का 'जैविक कार्बन' बना रहता था।आज इन अवशेषों को बेचने से किसानों को कुछ लाभ तो होता है, लेकिन वह रासायनिक उर्वरकों की वास्तविक लागत के मुकाबले बहुत कम है।

सरकार को चाहिए कि वह रासायनिक उर्वरकों के बैग का वजन कम कर उसकी जगह जैविक खाद के विकल्प उपलब्ध कराए।साथ ही, अत्यधिक उर्वरक उपयोग वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष निगरानी दल गठित किए जाने चाहिए।

धरती की सेहत सुधारने के लिए जरूरी सुझाव :-

1. हरी खाद का अधिक इस्तेमाल:जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है, उसी तरह से मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए हरी खाद अनिवार्य है।
2. पौधों का विकास:जैविक खाद के प्रयोग से पौधों की जड़ों को फैलने और गहराई तक जाने का पर्याप्त अवसर मिलता है।
3. वैज्ञानिक फसल चक्र:एक ही तरह की फसल बार-बार उगाने के बजाय फसल चक्र बदलें।जैसे दलहनी फसलें जमीन के गहरे स्तर से पोषक तत्व लेती हैं, जबकि गेहूं और धान ऊपरी सतह से।
4. उन्नत सिंचाई तकनीक:ड्रिप इरिगेशन (टपक सिंचाई) अपनाएं और खेती से पहले भूमि को समतल करें।इससे पानी की बचत होगी और उर्वरक सीधे पौधों पर कारगर तरीके से काम करेंगे।
5. यूरिया का कुशल उपयोग:यूरिया का छिड़काव शाम के समय अधिक प्रभावी होता है, जिससे कम खाद में बेहतर परिणाम मिलते हैं।
6. पशुधन और जैविक संतुलन:पशुपालन को बढ़ावा दें ताकि गोबर की खाद का उपयोग बढ़े।इससे उत्पादन क्षमता दीर्घकालिक बनी रहेगी और मिट्टी को भी विश्राम मिलेगा।

यदि हमने आज मिट्टी नहीं बचाई, तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। समय आ गया है कि हम रसायनों के इस मोह को छोड़कर प्रकृति की ओर लौटें।

-लेखक : पद्मश्री राम सरन वर्मा

बड़े पैमाने पर निर्माण, निश्चितता के साथ कार्य पूर्णता

एकीकृत प्रशासन कैसे भारत के अवसंरचना परिदृश्य को नया रूप दे रहा है

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

पिछले दशक में, भारत के अवसंरचना परिदृश्य में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ है—ऐसा बदलाव, जो केवल परिसंपत्ति निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन और सेवा अदायगी की संरचना तक विस्तारित है। पिछले चरणों की तुलना में इस दौर की विशेषता सिर्फ निवेश के पैमाने या कार्यान्वयन की गति से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि एक सुसंगत, परिणाम-उन्मुख प्रणाली उभर रही है, जो नीतिगत उद्देश्य, संघीय सहयोग और जमीन पर कार्यान्वयन के अनुरूप है।

विनायक पाई
(भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) महाराष्ट्र और राष्ट्रीय सड़क एवं राजमार्ग समिति के अध्यक्ष)

आज, भारत निर्णायक रूप से एक प्लेटफॉर्म-आधारित प्रशासन मॉडल की ओर आगे बढ़ रहा है—एक ऐसा मॉडल, जो अवसंरचना को अलग-अलग परियोजनाओं के समूह के बजाय एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में देखता है।

अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय, प्रणाली की सहायता से पैमाने का विस्तार

इस बदलाव का स्पष्ट प्रमाण है - राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, जो 2014 के लगभग 91,000 किमी से बढ़कर 2024 में 1.46 लाख किमी से अधिक हो गया है। निर्माण की गति में हुई वृद्धि का भी समान महत्व है, जो लगभग 12 किमी प्रति दिन से बढ़कर 34 किमी प्रति दिन से अधिक हो गई है।

इस गति को अक्सर एक तकनीकी उपलब्धि माना जाता है। वास्तव में, यह परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं का सहज रूप से समन्वय करने के बारे में है। यह एक ऐसी प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ बाधाओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है और समय पर समाधान किया जाता है।

सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से, परियोजनाओं के तेजी से पूरे होने का सीधा मतलब है - सामाजिक और आर्थिक लाभों की जल्द प्राप्ति – गांव, बाजारों से जुड़ते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा तक आसान पहुँच की सुविधा मिलती है और आपदा राहत गतिविधि एवं राष्ट्रीय सहनीयता मजबूत होती है। यह लॉजिस्टिक लागत को कम करके औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जवाबदेही को संस्थागत रूप देना: समीक्षा से समाधान तक

इस दशक की एक प्रमुख विशेषता है - समयबद्ध जवाबदेही को संस्थागत रूप देना। प्रगति (सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन) की शुरुआत से जटिल, अंतर-मंत्रालयी परियोजनाओं के प्रबंधन को एक नयी दिशा मिली।यहां

सबसे महत्वपूर्ण नीति संकेत सांस्कृतिक है: विलंब को अब सामान्य नहीं माना जाता और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से सौंपी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, बड़े और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं—जो कभी लंबे समय तक सुस्त पड़ी रहती थीं—अब पूर्वानुमान और अनुशासन के साथ प्रगति कर रही हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव, अवसंरचना परियोजनाओं में सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करना रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच नियमित व विभिन्न स्तरों पर संवाद ने कार्यान्वयन के माहौल को बदल दिया है, विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए जो कई क्षेत्रों में फैली होती हैं। यह मॉडल संवैधानिक भूमिकाओं का सम्मान करता है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए सामंजस्य सुनिश्चित करता है। राज्य अब केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि योजना, कार्यान्वयन और परिणाम प्रबंधन में सक्रिय साझेदार हैं। इसका परिणाम है - तेज सहमति निर्माण, कम कानूनी विवाद और जमीन पर सुचारु क्रियान्वयन।

उद्योग जगत के दृष्टिकोण से, यह पूर्वानुमान क्षमता कार्यान्वयन जोखिम को कम करती है। नीतिगत दृष्टिकोण से, यह भारत की संघीय कार्यान्वयन क्षमता में विश्वास को मजबूत करती है।

विविध प्रारूपों से जुड़ी योजना: परिसंपत्तियों से नेटवर्क तक

भारत की अवसंरचना रणनीति, परिवहन संपर्क से प्रतिस्पर्धा की ओर भी विकसित हो रही है। सड़कों की योजनायें अब केवल अंतिम बिंदुओं के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक लॉजिस्टिक्स और परिवहन इकोसिस्टम के रूप में बनायी जा रही हैं।

राजमार्गों का रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और शहरी परिवहन के साथ एकीकरण—जिसका समर्थन राष्ट्रीय योजना रूपरेखाओं, जैसे गति शक्ति द्वारा किया जा रहा है— ने भारत की लंबे समय से मौजूद संरचनात्मक चुनौतियों में से एक: उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, का समाधान करना शुरू कर दिया है। नीति निर्माताओं के लिए, यह बदलाव एक महत्वपूर्ण सबक को रेखांकित करता है।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु सक्रिय एवं कारगर निगरानी

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य वाहकों में से एक है। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा बेहतर सेवाओं के लिए निरंतर मांग पैदा करता है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत की विभिन्न परियोजनाओं के तेज विकास का एक आधार रहा है। सरकार पूरी प्राथमिकता के साथ इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। यह तथ्य इस वर्ष 11.1 लाख करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन और देश में समय पर विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करने वाली नीतियों की शुरुआत से स्पष्ट होता है। "मेक इन इंडिया", आत्मनिर्भर भारत, पीएम गतिशक्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लचीले नियमों और तकनीकी उन्नति जैसी अनुकूल नीतिगत पहलों के साथ, इस क्षेत्र के और भी तेजी से विकसित होने की उम्मीद है।

अल्केश कुमार शर्मा
(पीईएसबी के सदस्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव)

केरल और भारत सरकार में विभिन्न भूमिकाओं में तीस वर्षों से अधिक समय तक परियोजना कार्यान्वयन से जुड़े रहने और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं को संभालने के दौरान, मैंने विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न बाधाओं का सामना किया है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों में भूमि अधिग्रहण और नियामक संबंधी मंजूरियों से जुड़ी अनिश्चितताएं, व्यापक प्रारंभिक योजना एवं जोखिम प्रबंधन का अभाव और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे कारकों के लिए पर्याप्त योजना बनाने हेतु परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं की अपरिपक्वता शामिल हैं।

परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में बाधा डालने वाली अन्य समस्याओं में कच्चे माल की अनुपलब्धता, कुशल श्रमिकों (राजमिस्त्री, बढ़ई आदि) की अनुपलब्धता, पानी एवं बिजली की आपूर्ति का अभाव, अपूर्ण आरेख (ड्राइंग) उपलब्ध होना और डिजाइन में बार-बार होने वाले बदलाव शामिल हैं। स्थानीय समस्याओं और उचित परियोजना नियोजन एवं नियंत्रण के अभाव के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में देरी होती है और इससे अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से नकारात्मक असर पड़ता है।

बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाएं जटिल होती हैं तथा इनमें कई राज्यों, कई क्षेत्रों एवं कई एजेंसियों की भागीदारी होती है और इसके लिए विभिन्न केन्द्रीय व राज्य एजेंसियों से कई बार मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए समय की देरी और लागत में वृद्धि आम बात है।

यूं तो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अलग-अलग पद्धतियां और निगरानी तंत्र अपनाए गए, लेकिन वे एक-दूसरे से अलग-अलग काम करते लगे और उनके एवं राज्य सरकारों के बीच कोई कारगर समन्वय नहीं था।

मार्च 2015 में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक आईसीटी-आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म 'प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन' (प्रगति) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में होने वाली देरी को खत्म करने और आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और राज्य सरकारों द्वारा इंगित की गई परियोजनाओं की निगरानी करना भी था। प्रधानमंत्री ने 'प्रगति' को केन्द्र - केन्द्र और केन्द्र-राज्य समन्वय को बेहतर बनाने के एक व्यापक समाधान के रूप में तैयार किया। इसके शुभारंभ के समय उन्होंने कहा कि भारत में शासन को और अधिक कुशल एवं जवाबदेह बनना होगा तथा यह नया प्लेटफॉर्म उसी दिशा में एक कदम है। 'प्रगति' को तकनीक-आधारित एक ऐसी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया, जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की निगरानी करने, सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने और एक ही डिजिटल धरातल पर नागरिकों की शिकायतों का आकलन करने में सक्षम है।

शुरू से ही, 'प्रगति' के तंत्र ने विभिन केन्द्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से परियोजनाओं की निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 50 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव और केन्द्रीय विभागों के सचिव खास परियोजनाओं तथा योजनाओं में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से शामिल होते हैं। यह प्लेटफॉर्म एक आगे बढ़ने वाले फोरम के तौर पर भी काम करता है, जहां नियमित समस्याओं से मंत्रालय स्तर पर निपटा जाता है, जबकि जटिल मामलों को अंतिम समाधान के लिए प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता है।

शुरू से ही, 'प्रगति' के तंत्र ने विभिन केन्द्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से परियोजनाओं की निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 50 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव और केन्द्रीय विभागों के सचिव खास परियोजनाओं तथा योजनाओं में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से शामिल होते हैं। यह प्लेटफॉर्म एक आगे बढ़ने वाले फोरम के तौर पर भी काम करता है, जहां नियमित समस्याओं से मंत्रालय स्तर पर निपटा जाता है, जबकि जटिल मामलों को अंतिम समाधान के लिए प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता है।

भारतीय कृषि में मिट्टी की सेहत और टिकाऊ फसल उत्पादकता हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन

एक हरे-भरे भविष्य का निर्माण : भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की जरूरत

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

दशकों से, भारतीय कृषि की कहानी जबरदस्त विकास की रही है। लेकिन यह प्रगति हमारे सबसे अनमोल संसाधन - मिट्टी - की कीमत पर हुई है। आज जब हम बढ़ती आबादी और बदलते मौसम की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो रासायनिक उर्वरकों को लेकर "ज्यादा ही बेहतर है" वाला दृष्टिकोण काम नहीं आ रहा है। अपनी दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, भारत को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) की दिशा में आगे बढ़ना होगा। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एक ऐसी समग्र रणनीति है, जो हमारी जमीन की उर्वरता वापस लाने हेतु आधुनिक विज्ञान को पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ती है।

डॉ. कंचेती मृणालिनी
(वैज्ञानिक, आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, कानपुर, उत्तर प्रदेश)

पांव तले संकट : छोटे एवं सीमांत जोतों और नाइट्रोजन आधारित रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय कृषि की पहचान रही है। वर्षों तक असंतुलित उपयोग और लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी का काफी क्षरण हुआ है। अब हम "विभिन्न पोषक तत्वों की कमी" की समस्या से दो-चार हैं और इसकी वजह से मिट्टी में गंधक (सल्फर), जस्ता (जिंक) और बोरोन जैसे द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत अधिक कमी हो गई है।

जब मिट्टी की सेहत खराब होती है, तो "कारक उत्पादकता" भी कम हो जाती है - मतलब यह कि किसानों को पूर्व में उर्वरकों के कम इस्तेमाल से हासिल होने वाली पैदावार के बराबर उपज पाने हेतु अधिक उर्वरक डालना पड़ता है। उर्वरकों के इस्तेमाल का यह चक्र उत्पादन की लागत बढ़ा देता है और भारत की जलवायु में बेहद आम होते जा रहे अनियमित वर्षा एवं सूखे की स्थिति में फसलों को और अधिक नाजुक बना देता है।

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है?

आईएनएम का मतलब आधुनिक उर्वरकों के उपयोग को त्यागना नहीं, बल्कि जैविक एवं जीव विज्ञान संबंधी स्रोतों के साथ मिलाकर उनका अधिक समझदारी से इस्तेमाल करना है। यह मिट्टी के लिए एक संतुलित "आहार" जैसा है, जिसमें शामिल होते हैं:

- रासायनिक उर्वरक: मिट्टी की वास्तविक जरूरतों के आधार पर सही मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं।
- जैविक खाद: खेत की खाद (एफवाईएम), कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट और हरी खाद का इस्तेमाल करना।
- जैव उर्वरक (बायो-फर्टिलाइजर): नाइट्रोजन की मात्रा को प्राकृतिक रूप से सही करने और फास्फोरस को घुलनशील बनाने हेतु राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और माइकोराइजा जैसे लाभदायक रोगाणुओं का उपयोग करना।
- फसलों के अवशेष: उगाए गए पदार्थों को पुनर्चक्रित करके वापस धरती में मिला देना।

मिट्टी की सेहत के आधार : आईएनएम के कारगर होने की वजह को समझने के लिए हमें मिट्टी की सेहत के तीन मुख्य आधारों - भौतिक, रासायनिक और जैविक - को देखना होगा।

- **भौतिक :** आईएनएम मिट्टी की बनावट और पानी रोकने की क्षमता को बेहतर बनाता है। वर्षा पर निर्भर कृषि वाले इलाके के किसानों के लिए, इसका मतलब यह है कि मिट्टी स्पंज की तरह काम करती है और सूखे की अवधि में अधिक समय तक नमी बनाए रखती है।
- **रासायनिक :** यह पीएच के स्तर को संतुलित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वृहद् एवं सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में अटके रहने या बह जाने के बजाय असल में पौधों की जड़ों को मिलें।
- **जैविक :** शायद सबसे जरूरी बात यह है कि आईएनएम सूक्ष्मजीवों की विविधता और केंचुओं की आबादी को बढ़ाता है। ये "छोटे इंजीनियर" पोषक तत्वों के चक्रण और चावल-गेहूं या गन्ने बेल्ट जैसी गहन प्रणालियों में उत्पादकता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होते हैं।

भारतीय किसानों के लिए उत्कृष्ट कार्यप्रणाली : आईएनएम को प्रयोगशाला से खेत तक ले जाने के लिए व्यावहारिक तथा स्थान की जरूरतों के अनुरूप खास रणनीतियों की आवश्यकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी राष्ट्रीय पहल पहले से ही अनुमान के बजाय मिट्टी की असली जांच के आधार पर उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह देकर एक रास्ता बता रही हैं।

प्रबंधन के मुख्य तरीकों में फसल के विकास के अहम चरण के हिसाब से नाइट्रोजन को बांटकर डालने और नीम-कोटेड यूरिया जैसे धीरे-धीरे छोड़े जाने वाले विकल्प का इस्तेमाल शामिल है।

नया कानून पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक सुरक्षा का ढांचा स्थापित करता है : राजेंद्र चौधरी

• **जालंधर ब्रीज** . चंडीगढ़/अंबाला

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो के अपर महानिदेशक (ग्रामीण विकास) राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 'विकसित भारत - जी राम जी' कानून विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है भारत में आत्मनिर्भर गाँवों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है । हरियाणा के अंबाला में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 पर आयोजित वार्तालाप को संबोधन करते हुए पत्र सूचना कार्यालय, दिल्ली में अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने इस महत्वाकांक्षी पहल के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि यह कानून रोजगार सृजन को मज़बूती देने, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और गाँवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास है।

उन्होंने कहा कि पहले की व्यवस्था में मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी तो थी, लेकिन कई स्थानों पर न तो समय पर काम मिल पाता था और न ही मज़दूरी का भुगतान समय पर हो पाता था। इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कमियों को दूर करने और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार ने 'विकसित भारत - जी राम जी' क़ानून के माध्यम से सुधार किए हैं।

उन्होंने बताया कि नए क़ानून के तहत रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मज़दूरों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि मज़दूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो उस पर ब्याज भी दिया जाएगा।

चौधरी ने कहा कि नए क़ानून के तहत ग्राम पंचायत को सशक्त बनाया गया है, और अब गाँव की सभाएँ स्वयं तय करेंगी कि उनके गाँव में कौन-से विकास कार्य कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि विकास से संबंधित निर्णय अब गाँव स्तर पर ही लिए जाएँगे। चौधरी ने कहा विकसित भारत- रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025, भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक निर्णायक बदलाव का

प्रतिनिधित्व करता है। नया कानून एक आधुनिक, जवाबदेह और अवसंरचना-केंद्रित ढांचे को मजबूती प्रदान करता है। इस मौके पर अंबाला के उपायुक्त एवं कार्यक्रम के मुख्यातिथि अजय सिंह तोमर ने कहा कि नया कानून एक आधुनिक, जवाबदेह और अवसंरचना-केंद्रित ढांचे के माध्यम से उनकी कमियों को दूर करते हुए पिछले सुधारों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि गारंटीकृत रोजगार का विस्तार करके, राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और कार्यों के बीच ताल-मेल बिठाते हुए मजबूत डिजिटल शासन को शामिल करके, यह कानून ग्रामीण रोजगार को सतत विकास और यथोचित आजीविका के लिए एक कार्यनीतिक साधन के रूप में स्थापित करता है, जो पूरी तरह से विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जुड़ा हुआ है।

तोमर ने बताया कि 125 दिनों के रोजगार की गारंटी घरेलू आय को बढ़ाती है, ग्राम-स्तर की खपत को प्रोत्साहित करती है, और डिजिटल उपस्थिति, मजदूरी भुगतान और डेटा-संचालित योजना के माध्यम से प्रवासन को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मीडिया से आहवान किया कि इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक करें और यदि कोई भी व्यक्ति इस कानून के बारे में भ्रमक भ्रांति फैलाता है तो मीडिया तथ्यों पर आधारित उसका सकारात्मक जवाब प्रस्तुत करें ।

इससे पहले कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए पीआईबी चंडीगढ़ के मीडिया एवं संचार अधिकारी अहमद खान ने वार्तालाप कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह कार्यशाला मीडिया और सरकार के बीच सेतु का काम करती है। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने पीआईबी की अनुसंधान इकाई द्वारा विभिन्न विषयों पर किए जा रहे विश्लेषण और तथ्य परक सूचनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने इन विश्लेषक से जी राम जी एक्ट पर महत्वपूर्ण विश्वसनीय आंकड़ों एवं जानकारियों का उपयोग अपने लेख और समाचार लेखन में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर विराट, अतिरिक्त उपायुक्त, अंबाला ने योजना के विभिन्न प्रावधानों और विकसित भारत के लक्ष्य में ग्रामीण विकास की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही समावेशी और सतत विकास विकसित राष्ट्र की आधारशिला है।

इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ गगनदीप सिंह ने भी विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 के तहत महत्वपूर्ण जानकारी दी और कहा कि इस कानून के लागू होने से किसान व मजदूर को लाभ होगा, दोनों सशक्त और मजबूत भी होगे।

इस अवसर पर अंबाला के लोग संपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने मीडिया कर्मियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों का धन्यवाद प्रस्तुत किया । इस मौके पर एसीयूटी राहुल कनवरिया व जिला के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गणतंत्र दिवस: डिप्टी कमिश्नर ने जिला स्तरीय समागम की रिहर्सल का लिया जायजा

कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज, डिप्टी कमिश्नर ने जालंधर वासियों को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समागम में बढ़-चढ़कर पहुंचने का दिया न्योता

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने गणतंत्र दिवस मौके पर 26 जनवरी को स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय समागम की चल रही रिहर्सल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर समागम में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा पेश किए जाने वाले देश भक्ति की भावना पर आधारित सांस्कृतिक प्रोग्राम की रिहर्सल को देखा और विद्यार्थियों एवं उनके अध्यापकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को पूर्ण ऊर्जा, अनुशासन और आत्म विश्वास के साथ अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए उत्साहित किया ताकि समागम को यादगार बनाया जा सके। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जिला स्तरीय समागम के दौरान पंजाब के माइंस एंड जियोलॉजी, जल संसाधन एवं भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और ध्वजारोहण की रस्म अदा करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समागम के दौरान विभिन्न टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। जबकि विभिन्न विभागों द्वारा पंजाब सरकार की लोक कल्याण योजनाओं को दर्शाती हुई झांकियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा मास पी.टी. शो के अलावा देश भक्ति की भावना से भरा सांस्कृतिक समागम पेश किया जाएगा।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि समागम के दौरान देश के आजादी संग्राम में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों के शानदार कार्य प्रदर्शन वाले अधिकारियों/कर्मचारियों और विभिन्न क्षेत्रों में नाम रौशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित करने के साथ-साथ जिला स्तरीय समागम के दौरान सर्वोत्तम सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा सर्वोत्तम झांकी को भी सम्मानित किया जाएगा।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा देश भक्ति की भावना, उच्च मापदंडों और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समागम को उचित ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जा रहे है, जिसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटियां पहले ही लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने जालंधर वासियों को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समागम में बड़ी संख्या में पहुंचने का न्योता दिया।

सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत मुकेरियां में स्कूल बसों की जांच, 81 बसें चेक व 13 के काटे चालान

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

सेफ स्कूल वाहन नीति के अंतर्गत जिला होशियारपुर के ब्लॉक मुकेरियां में स्कूल बसों की व्यापक जांच की गई। यह कार्रवाई माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर के आदेशों के अनुसार की गई। ज़िला बाल सुरक्षा अधिकारी हरप्रीत कौर ने बताया कि 21 जनवरी 2026 को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, एस.पी.एन.एस.एस.के पब्लिक हाई स्कूल, वुडबेरी वर्ल्ड स्कूल एवं कैम्ब्रिज ओवरसीज स्कूल की बसों की जांच की गई। जांच के दौरान कुल 81 स्कूल बसों को चेक किया गया, जिनमें से नियमों का उल्लंघन करने पर 13 बसों के चालान काटे गए।

जांच के दौरान कई बसों में एक्सपायर्ड फर्स्ट एड किट, फॉग लाइट्स का अभाव, लेडी अटेंडेंट की नियुक्ति न होना, बिना पासिंग के वाहन, स्पीड गवर्नर का न होना, इमरजेंसी एग्जिट की कमी, अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे का अभाव, निर्धारित बैठने की क्षमता से अधिक सवारियां जैसी गंभीर खामियां पाई गईं। इस अभियान में जिला बाल सुरक्षा यूनिट से रणजीत कौर, जसविंदर सिंह, पुलिस विभाग से एएसआई राकेश कुमार, एएसआई गुरनाम सिंह तथा शिक्षा विभाग से सुरजीत सिंह सहित पूरी टीम उपस्थित रही। टीम द्वारा विभिन्न स्कूलों में सेफ स्कूल वाहन नीति के प्रति जागरूकता भी फैलाई गई।

जालंधर में 2 स्कूल बसों के चालान

जालंधर (जालंधर ब्रीज). जिला बाल सुरक्षा अधिकारी अजय भारती और जिला प्रोग्राम ऑफिसर मनजिंदर सिंह की लीडरशिप में स्कूल गाड़ियों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करने वाली 2 स्कूल बसों के चालान काटे गए। इस कैंपेन के दौरान ए.पी.जे. स्कूल, एम.जी.एन. स्कूल, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, पुलिस डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, आई.वी.वाई. स्कूल और मेयर वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की स्कूल बसों समेत करीब 17 स्कूल बसों के दस्तावेज चेक किए गए। इस दौरान स्कूल बसों के ड्राइवरों को सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी की शर्तों के बारे में जागरूक किया गया। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी की शर्तों को पूरा नहीं करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल गाड़ियों के ड्राइवरों के पास गाड़ी के पूरे दस्तावेज होने चाहिए। इस मौके पर संदीप कुमार, गौरव कुमार, कंचन और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज भी मौजूद थे।

सड़क सुरक्षा माह के तहत क्षेत्रीय परिवहन दफ्तर द्वारा बाइक रैली

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

आम लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह-2026 के तहत गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन दफ्तर द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जिसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमनपाल सिंह, रिटायर्ड एस.एस.पी. एम.एस. भुल्लर ज्वाइंट डायरेक्टर लीड एजेंसी ऑन रोड सेफ्टी, ए.डी.सी.पी. हरमिंदर सिंह गिल, सी.एम.एफ.ओ. नवदीप सिंह और सहायक कमिश्नर (ज) रोहित जिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम से शुरू हुई यह बाइक रैली चुनमुन मॉल से ए.पी.जे. स्कूल, बीएसएफ चौक से होते हुए वापिस स्टेडियम में समाप्त हुई। यह रैली महिलाओं के राइडर्स ग्रुप 'पंजाब राइडर्स' के सहयोग से निकाली गई, जिसमें 15 महिला बाइकर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अमनपाल सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की हिदायतो पर मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा महीने के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए अलग-अलग गतिविधियां करवाइ जा रही हैं, जिस तहत आज वुमेन बाइक रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि इस बाइक रैली का उद्देश्य लोगों को जिम्मेदार ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क करना था। उन्होंने बताया कि इस से पहले विभाग द्वारा ट्रक, टैक्सी और ऑटो यूनियनों, स्कूली बसों के ड्राइवरों और आम लोगों को ट्रैफिक नियमों से जानकार करवाने के लिए जागरूकता सेमिनार करवाए गए है।

सरकार का 12 हजार यूथ क्लब बंद करने का फैसला युवाओं से सीधा धोखा : झिंजर

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

यूथ अकाली दल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंजर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पंजाब भर के करीब 12 हजार यूथ क्लबों को बंद करने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह कदम युवाओं की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। झिंजर ने कहा कि पंजाब में कुल करीब 14 हजार यूथ क्लब मौजूद हैं, जो गांवों के युवाओं को खेलों, सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उन्हें नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पांच साल और आम आदमी पार्टी के चार साल के शासनकाल में युवाओं से सिर्फ वादे ही किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया। दोनों सरकारें हर मोर्चे पर पंजाब में विफल साबित हुई हैं।

सवाल उठाते हुए झिंजर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बताएं कि पिछले चार वर्षों में यूथ क्लबों को कितनी ग्रांट दी गई? कितने क्लबों को खेल किट, जिम का सामान या अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं? अगर सरकार ने कभी यूथ क्लबों को सहयोग ही नहीं दिया, तो उन्हें "निष्क्रिय" कहने का आधार क्या है?

झिंजर ने कहा कि यूथ क्लब आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ही उन्हें मजबूत बनाने और सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब जानबूझकर क्लबों को भंग कर अपने चहेतों के नाम पर उन्हें दोबारा पंजीकृत करने की साजिश रची जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख आम आदमी पार्टी को गांवों के यूथ क्लब याद आ रहे हैं। यह पूरा मामला सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। अगर सरकार सच में युवाओं की भलाई चाहती, तो पिछले चार वर्षों में यूथ क्लबों के लिए पर्याप्त फंड, रोजगार से जुड़ी योजनाएं और खेल-सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाते।

दिल्ली की अदालत द्वारा ईडी केस में केजरीवाल बरी : अमन अरोड़ा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति मामले से संबंधित इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के एक मामले में बरी करने के दिल्ली की अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए 'आप' पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि एक बार फिर, झूठ, धोखे और राजनीतिक बदलाखोरी पर सच्चाई की जीत हुई है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि लंबे समय से भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल और 'आप' के अन्य नेताओं के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद केस दर्ज करने के लिए ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य 'आप' की छवि को खराब करना और केजरीवाल की राजनीति को कमजोर करना था। उन्होंने आगे कहा कि आज के अदालती फैसले ने इन कोशिशों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल का बरी होना साबित करता है कि आरोप मनगढ़ंत और सियासत से प्रेरित थे। अमन अरोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार का इरादा कभी भी इंसाफ करना नहीं था, यह सिर्फ हमारे राष्ट्रीय संयोजक को परेशान और बदनाम करना था।

अमन अरोड़ा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा को आज के फैसले से सबक सीखना चाहिए और ऐसी दमनकारी और बदलाखोरी वाली राजनीति को खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र डराने-धमकाने और झूठे केसों पर टिका नहीं रह सकता। जनता सब देख रही है और सच हमेशा सामने आता है।

बाल भिक्षा रोकू टास्क फोर्स ने भिक्षा मांगती बच्ची को छुड़ाया

जालंधर (जालंधर ब्रीज). जिला स्तरीय बाल भिक्षा रोकू टास्क फोर्स द्वारा आज कपूरथला चौक और चिकचिक चौक पर छापेमारी की गई, जिस दौरान भीख मांगती एक बच्ची को रेस्क्यू किया गया। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी अजय भारती ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि बाल भिक्षा मांगने को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्त्री एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे जीवनजोत प्रोजेक्ट के तहत यह चेकिंग की गई है, जिस दौरान एक नाबालिग लड़की को छुड़ाने उपरांत उसका मैडिकल करवाया गया है। उन्होंने बताया कि लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने उपरांत चिल्ड्रन होम गांधी वनिता आश्रम में शेल्टर प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि बच्ची के माता-पिता के बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होने के बाद अगली कार्यवाही आरंभ की होगी।

जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा : मोहिंदर भगत

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

ठंड के मौसम के मदेनजर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत द्वारा आज भार्गव कैंप में जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल, ट्रैक सूट और बूटों का वितरण किया गया। मानवता की सेवा के इस उपक्रम के दौरान डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल भी मौजूद थे।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि हम सबका फर्ज बनता है कि मुश्किल हालात का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के कल्याण सहित प्रत्येक वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए लगातार उपक्रम कर रही है।

भगत ने लोगों से भी अपील की कि अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस मौके पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव सुरजीत लाल और अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे।

हाई-रिस्क मामलों के फॉलो-अप के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश

जालंधर (जालंधर ब्रीज). डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर पंजाब डॉ. अदिति सलारिया की अध्यक्षता में नवंबर-2025 माह के दौरान राज्य में हुई मातृ मृत्यु (मैटर्नल डेथ्स) के मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एम.डी.आर. मीटिंग में समीक्षा की गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग ने नवंबर माह के दौरान जिला जालंधर में हुई एक मातृ मृत्यु के कारणों के बारे में जानकारी दी तथा भविष्य में मातृ मृत्यु के कारणों पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसी मौतों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

वीसी मीटिंग के बाद सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और स्वास्थ्य स्टाफ के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए कि हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए एक्शन प्लान तैयार कर उसका निरंतर फॉलो-अप किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एनीमिया, बी.पी., शुगर और पोस्ट पार्टम हैमरेज (पी.पी.एच.) आदि कारणों से किसी भी गर्भवती महिला की मृत्यु न हो तथा सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके।

एसडीएच फिल्लौर के लिए सर्जन को मेडिकल सेवाएं प्रदान करने हेतु इम्पैनल किया

जालंधर (जालंधर ब्रीज). सब-डिविजनल अस्पताल फिल्लौर में सर्जन के रिक्त पद को भरने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय जालंधर में इंटरव्यू/काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई। इस प्रक्रिया के दौरान एक योग्य उम्मीदवार का चयन कर उसे एसडीएच फिल्लौर के लिए इम्पैनल किया गया। सिविल सर्जन जालंधर डॉ. राजेश गर्ग ने बताया कि यह चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की गई। इंटरव्यू के लिए कुल चार उम्मीदवार उपस्थित हुए, जिनके मूल दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई और योग्यता के आधार पर चयन को अंतिम रूप दिया गया। चयनित सर्जन को नियुक्ति पत्र सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉ. जसविंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर डॉ. रमन गुप्ता और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉ. राकेश चोपड़ा भी उपस्थित थे। डॉ. राजेश गर्ग ने कहा कि इस नियुक्ति से एस.डी.एच. फिल्लौर में सर्जिकल सेवाएं और अधिक सशक्त होंगी तथा क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।

कपूरथला के 561 गांवों के खसरों का होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे : डिप्टी कमिश्नर

कपूरथला (जालंधर ब्रीज). डिप्टी कमिश्नर कपूरथला अमित कुमार पंचाल ने बताया कि कपूरथला ज़िले के गांवों का डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) कराया जा रहा है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि ज़िला कपूरथला के अंतर्गत तहसील/सब-तहसील स्तर पर 561 गांवों के खसरों का डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने के लिए निजी सर्वेयरों को (मानदेय के आधार पर 10/- रुपये प्रति सत्यापित खसरा/प्लॉट) नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 26 जनवरी 2026 को शाम 5.00 बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार https://kapurthala.gov.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रफॉर्मा को डाक के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से (डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, जिला प्रशासनिक परिसर, कपूरथला) या इस कार्यालय की ई-मेल आईडी deskapurthala@gmail.com पर निर्धारित तिथि तक भेज सकते हैं। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। डीसीएस के दौरान डेटा एकत्र करने के लिए उम्मीदवार को एंड्रॉयड फोन पर मोबाइल एप्लीकेशन चलाने की जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवार कार्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। विज्ञापन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/सूचना केवल वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी।

राज्यसभा सदस्य संत सीचेवाल द्वारा डिजिटल एक्स-रे मशीन का उद्घाटन

कपूरथला (जालंधर ब्रीज). सिविल अस्पताल कपूरथला में राज्यसभा सदस्य संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल द्वारा डिजिटल एक्स-रे मशीन का औपचारिक उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि सिविल अस्पताल द्वारा डिजिटल एक्स-रे मशीन की मांग की गई थी, जिसे राज्यसभा सदस्य ने सांसद निधि से उपलब्ध करवा दिया था। आज संत सीचेवाल द्वारा इस मशीन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य ने कहा कि वे लोगों से जुड़े मुद्दों, विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित, किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में उपकरणों या मशीनरी की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों के हित को सर्वोपरि रखते हुए हर वर्ग के लिए 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने के उद्देश्य से यह स्वास्थ्य योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के शुरू होने से हर वर्ग के लोग इसके लाभार्थी बनेंगे। सिविल सर्जन डॉ. संजीव भगत ने कहा कि यह डिजिटल मशीन मरीजों के लिए वरदान साबित होगी।

बांग्लादेश आईसीसी टी20 टूर्नामेंट से बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने गुरुवार को पुष्टि की कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा बांग्लादेश के विश्व कप मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बाद भी बीसीबी भारत में आईसीसी पुरुष विश्व कप मैच न खेलने के अपने निर्णय पर अडिग है। आईसीसी ने बुधवार को आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए बीसीबी के मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित करने के अनुरोध को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अस्वीकार कर दिया। यह कॉन्फ्रेंस आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। टी20 विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होगा, जिसकी सह-मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे।

बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने पत्रकारों से कहा हम आईसीसी के साथ बातचीत जारी रखेंगे। हम विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में नहीं खेलेंगे। हम संघर्ष करते रहेंगे। आईसीसी बोर्ड की बैठक में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए गए। मुस्तफिजुर का मामला कोई अलग-थलग मुद्दा नहीं है। उस मामले में (भारत) एकमात्र निर्णय लेने वाला था।

जिक्रयोग्य है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बुधवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उस विवादास्पद अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें आगामी टी20 विश्व कप के अपने मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि टूर्नामेंट अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और स्थलों पर ही आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे क्योंकि भारत में टूर्नामेंट के किसी भी स्थल पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों, अधिकारियों या प्रशंसकों की सुरक्षा को कोई विश्वसनीय खतरा नहीं है।

आईसीसी बोर्ड की यह बैठक विशेष रूप से बांग्लादेश की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। आईसीसी ने बीसीबी को अल्टीमेटम दिया था कि अगर वह भारत नहीं आते, तो उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। अब बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया है। ऐसे में स्कॉटलैंड की टीम के लिए रास्ता खुल गया है।

बाजवा ने लुधियाना में ड्रग त्रासदी की पीड़ित महिला से मुलाकात की, ऑपरेशन प्रहार को दिखावटी तमाशा बताया

लुधियाना (जालंधर ब्रीज). पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने लुधियाना ज़िले के सिद्धवां बेट के पास स्थित शेरावाला गांव का दौरा कर उस महिला से मुलाकात की, जिसने नशे की लत और ओवरडोज़ के कारण अपने छह के छह बेटों को खो दिया। बाजवा ने इस त्रासदी को पंजाब में नशा रोकने में आम आदमी पार्टी सरकार की पूरी विफलता का दिल दहला देने वाला प्रमाण बताया।

बाजवा ने पीड़ित महिला के घर जाकर परिवार को हुई अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार में छह बेटों की मौत सरकार के नशा नियंत्रण को लेकर किए गए बड़े-बड़े दावों की सच्चाई को उजागर करती है। दौरे के दौरान बाजवा ने तात्कालिक राहत के रूप में पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता भी दी और निरंतर सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने एनआरआई और दुनिया भर में बसे पंजाबी प्रवासी समुदाय से भी अपील की कि वे नशों से तबाह हो चुके परिवारों की मदद के लिए आगे आएं। "पंजाब के एनआरआई हमेशा संकट के समय अपने लोगों के साथ खड़े रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे नशा महामारी से उजड़े और राज्य द्वारा छोड़े गए परिवारों की सहायता करें," बाजवा ने कहा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, J7 NEAR BUS STAND SUBHANPUR (HAMIRA), KAPURTHALA, PUNJAB - 144808, and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.